



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4

PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 373]

नई दिल्ली, बुधवार, अक्टूबर 30, 2019/कार्तिक 8, 1941

No. 373]

NEW DELHI, WEDNESDAY, OCTOBER 30, 2019/KARTIKA 8, 1941

## महापत्तन प्रशुल्क प्राधिकरण

### अधिसूचना

मुम्बई, 22 अक्टूबर, 2019

**सं. टीएएमपी/32/2019-सीसीटीपीएल.**—महापत्तन न्यास अधिनियम, 1963 (1963 का 38) की धारा 48 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए महापत्तन प्रशुल्क प्राधिकरण एतद्वारा चेन्नई कंटेनर टर्मिनल प्राइवेट लिमिटेड (सीसीटीपीएल) से प्राप्त सीधे पत्तन प्रवेश (डीपीई) निर्यात कंटेनरों के निशुल्क दिवसों में वृद्धि को अपने दरमानों में अंतर्विष्ट करने के प्रस्ताव का, इसके साथ संलग्न आदेश के अनुसार, निपटान करता है।

### महापत्तन प्रशुल्क प्राधिकरण

### मामला सं. टीएएमपी/32/2019-सीसीटीपीएल

चेन्नई कंटेनर टर्मिनल प्राइवेट लिमिटेड

---

आवेदक

### गणपूर्ति

- (i). श्री टी.एस.बालसुब्रमनियन, सदस्य (वित्त)
- (ii). श्री रजत सच्चर, सदस्य (आर्थिक)

### आदेश

(अक्टूबर, 2019 के 10वें दिन पारित)

मामला चेन्नई कंटेनर टर्मिनल प्राइवेट लिमिटेड (सीसीटीपीएल) से प्राप्त सीधे पत्तन प्रवेश (डीपीई) निर्यात कंटेनरों के निशुल्क दिवसों में वृद्धि को उनके दरमानों में अंतर्विष्ट करने के प्रस्ताव से संबंधित है।

2.1. सीसीटीपीएल के दरमानों का पिछला संशोधन इस प्राधिकरण द्वारा 25 मार्च 2011 के आदेश संख्या टीएएमपी/55/2009- सीसीटीपीएल द्वारा किया गया था जिसमें तत्समय प्रचलित प्रशुल्क पर (यानी 19 जून, 2008 के आदेश संख्या टीएएमपी/45/2007-सीसीटीपीएल में अनुमोदित) अक्रास दा बोर्ड 35% घटौती प्रभावित की गई थी।

सीसीटीपीएल ने अपनी रिट याचिका संख्या 2011 के 12456 और 12457 के द्वारा 25 मार्च 2011 के प्रशुल्क आदेश को माननीय मद्रास उच्च न्यायालय से संपर्क किया। माननीय उच्च न्यायालय ने 25 मार्च 2011 के आदेश पर रोक लगा दी और सीसीटीपीएल को 19 जून, 2008 को अनुमोदित प्रशुल्क की उगाही जारी रखने की अनुमति दे दी।

2.2. इस पृष्ठभूमि में, सीसीटीपीएल अब 19 जून, 2008 के आदेश संख्या टीएमपी/45/2007-सीसीटीपीएल द्वारा यथाअनुमोदित सीसीटीपीएल के दरमानों के खंड 3.11 में निर्धारित भंडारण अनुसूची में संशोधन के प्रस्ताव के साथ आया है।

3.1. सीसीटीपीएल द्वारा 24 जून, 2019 के पत्र के द्वारा निम्नलिखित निवेदन किये हैं:

- (i) सीधे पत्तन प्रवेश स्कीम व्यापार सुविधा के एक उपाय के रूप में, निर्यात कंटेनरों के निकासी समय को कम करने तथा फैक्ट्री से भरे गये/स्वः सील किये गये कंटेनरों को एलईओ से पूर्व सीधे टर्मिनलों में मूव करने के लिये केंद्रीय प्रत्यक्ष कर और सीमाशुल्क बोर्ड के (07.09.2016) के परिपत्र संख्या एफ 450/2009-सीमा शुल्क-IV के द्वारा लागू की गई एक नई स्कीम है।
- (ii) फिर भी, निर्यातकों के लिये उत्पादन बनाम शिपमेंट के प्रेषण प्रबंधन में सुविधा का उपयोग एक चुनौती बन रहा है विशेषकर तब जब शिपमेंट में अनेकों कंटेनर और बिल निहित हों। जब शिपमेंट/कंटेनरों एक भाग प्रेषण के लिये तैयार हो शेष अभी भी तैयार किये जा रहे हों। तब कंटेनरों/कार्गो को भंडार में रखना ही पड़ेगा ताकि बाद में उन्हें एक साथ भेजा जा सके या अन्यथा प्रेषण में विलम्ब किया जाये, जिसके लिये फैक्ट्री में अतिरिक्त भंडार स्थान और प्रेषण क्षमता की जरूरत पड़ती है। परिणामस्वरूप निर्यातकों की लागतें और कठिनाईयां बढ़ती हैं।
- (iii). उक्त स्थिति से बचने के लिये डीपीई ग्राहकों ने सीसीटीपीएल को निशुल्क भंडारण अवधि को 07 दिन से बढ़ा कर 15 दिन करने का अनुरोध किया ताकि प्रेषण कार्गो/कंटेनर बिना किसी अतिरिक्त भंडारण प्रभार के निरंतर आधार पर भेजा जा सके।
- (iv). आस पास के छोटे पत्तन, जो प्राधिकरण के प्रशुल्क व्यवस्था के अंतर्गत नहीं आते, डीपीई ग्राहकों को 30 दिन तक की स्वतंत्रता देते हैं जो अधिकतर डीपीई ग्राहकों को अपने कंटेनरों को ऐसे निजी पत्तनों को परिवर्तित करने को प्रभावित करते हैं।
- (v). सीसीटीपीएल के अनुसार वर्तमान दरमानों के खंड 3.11, के अनुसार निर्यात कंटेनर भंडारण की 07 दिन की निशुल्क अवधि के पात्र हैं। इस प्रकार, सीआईटीपीएल ने डीपीई ग्राहकों के लिए निशुल्क अवधि को वर्तमान 7 दिन से बढ़ाकर 15 दिन करने का प्रस्ताव किया है।

3.2. सीटीपीएल का प्रस्ताव अपने दरमानों के भाग 3.11 के भंडारण अनुसूची में क्रमांक 2(क) के रूप में नई प्रविष्टि करने का है। वर्तमान और भंडारण अनुसूची की तुलनात्मक स्थिति इस प्रकार है:-

(क). वर्तमान स्थिति

क्र.सं	विवरण	विदेशगामी पोत			तटीय पोत		
		दर प्रति कंटेनर प्रति दिन या उसका भाग (अमरीकी डॉलर में)			दर प्रति कंटेनर प्रति दिन या उसका भाग (रु.में)		
2	निर्यात- एफसीएल, एलसीएल एवं खाली	20' तक	20'से अधिक और 40' तक	40'से अधिक	20' तक	20'से अधिक और 40' तक	40'से अधिक
	0-7 दिन	निशुल्क	निशुल्क	निशुल्क	निशुल्क	निशुल्क	निशुल्क
	8-15 दिन	5.50	11.00	16.50	231.00	462.00	693.00
	16-30 दिन	11.00	22.00	33.00	462.00	924.00	1386.00

	30 दिन से आगे	22.00	44.00	66.00	924.00	1848.00	2772.00
--	------------------	-------	-------	-------	--------	---------	---------

(ख). प्रस्तावित उपबंध:

क्र.सं.	विवरण	विदेशगामी पोत			तटीय पोत		
		दर प्रति कंटेनर प्रति दिन या उसका भाग (अमरीकी डॉलर में)			दर प्रति कंटेनर प्रति दिन या उसका भाग (रु.में)		
2	निर्यात- एफसीएल, एलसीएल एवं खाली	20' तक	20' से अधिक और 40' तक	40' से अधिक	20' तक	20' से अधिक और 40' तक	40' से अधिक
	0-7 दिन	निशुल्क	निशुल्क	निशुल्क	निशुल्क	निशुल्क	निशुल्क
	8-15 दिन	5.50	11.00	16.50	231.00	462.00	693.00
	16-30 दिन	11.00	22.00	33.00	462.00	924.00	1386.00
	30 दिन से आगे	22.00	44.00	66.00	924.00	1848.00	2772.00
2.1	निर्यात- सीधे पत्तन प्रवेश कंटेनर (डीपीई)						
	0-15 दिन	निशुल्क	निशुल्क	निशुल्क	निशुल्क	निशुल्क	निशुल्क
	16-30 दिन	11.00	22.00	33.00	462.00	924.00	1386.00
	30 दिन से आगे	22.00	44.00	66.00	924.00	1848.00	2772.00

3.3. बाद में, सीसीटीपीएल ने 06 अगस्त, 2019 के अपने ई-मेल के द्वारा यह संसूचित किया कि तटीय पोतों के संदर्भ में प्रभार संगत नहीं है और अनुरोध किया कि उसके द्वारा यथाप्रस्तावित तटीय पोतों के प्रभार निर्धारण को छोड़ दिया जाये तथा विदेशगामी पोतों के माध्यम से मूव होने वाले कंटेनर के लिये अतिरिक्त निशुल्क दिवसों के प्रस्ताव को अनुमोदित किया जाये।

4.1. सीसीटीपीएल के प्रस्ताव को हमारे 27 जून, 2019 के पत्र के द्वारा लाइसेंस प्रदाता पत्तन यानी चेन्नई पत्तन न्यास (सीएचपीटी) को उनकी टिप्पणियों के लिए भेजा गया।

4.2. प्रत्युत्तर में, सीएचपीटी ने 16 जुलाई, 2019 के ई-मेल द्वारा निम्नलिखित संसूचना दी:

- (i). चेन्नई पत्तन के दोनों टर्मिनलों में निर्यात कंटेनरों की वृद्धि कट्टुप्पल्ली और कृष्णापत्तनम पत्तनों से बढ़ रही प्रतिस्पर्धा से प्रभावित हुई है क्योंकि ये पत्तन चेन्नई पत्तन में प्रचालित पोतों को अपनी ओर आकर्षित करते हैं।
- (ii). अन्य पत्तनों में निजी कंटेनर टर्मिनल प्रचालक पोत संबंधी प्रभारों में भारी छूट और निशुल्क पार्किंग स्थान, डीपीई कंटेनरों के लिए अधिक भंडारण अवधि आदि जैसी अतिरिक्त सुविधाएं देकर करते हैं। निर्यात कंटेनर इन अतिरिक्त सुविधाओं की ओर सुगमता से आकर्षित हो जाते हैं मुख्यतः कट्टुप्पल्ली और कामराज पत्तन कंटेनर टर्मिनल पर सुगम पहुंच होती है और चूंकि यह पत्तन उन क्षेत्रों में स्थित हैं जहां सड़के भीड़-भाड़ वाली नहीं हैं शहरी यातायात से दूर है।
- (iii). इस प्रवृत्ति को रोकने के उपाय के एक भाग के रूप में, टर्मिनलों ने निर्यात कंटेनरों के भंडारण की निशुल्क अवधि को 7 से 15 तक बढ़ा दिया जाए। वे महसूस करते हैं कि इससे कुछेक निर्यातक कंटेनरों को पहले ही मूव कर पायेंगे और पोत कनैक्टिविटी सुनिश्चित करने के लिए वे समय पर चेन्नई टर्मिनल पहुंच पायें।
- (iv). इस समय, वे ऐसा कदम उठाने में सक्षम नहीं हैं क्योंकि चेन्नई टर्मिनल 7 दिन की निशुल्क अवधि से बंधे है जबकि निजी कंटेनर टर्मिनल चुनिंदा निर्यात ग्राहकों को 14-30 दिन की निशुल्क अवधि प्रदान करते हैं।

- (v). उपरोक्त को देखते हुए, सीसीटीपीएल के प्रस्ताव को व्यापार के हित को ध्यान में रखकर स्वीकार कर लिया जाए।

5.1. सीएचपीटी से प्राप्त टिप्पणियों के आधार पर, सीसीटीपीएल को तदर्थ आधार पर अनुमोदन संसूचित करते हुए 17 जुलाई, 2019 को पत्र संख्या टीएएमपी/55/2009-सीसीटीपीएल जारी किया गया था कि वह अपने दरमानों के खंड 3.11 (कंटेनर भंडारण प्रभार) में क्रमांक 2(क) अंतर्विष्ट कर ले, जैसा ऊपर पैरा 3.2(ख) में चर्चा की गई है। सीसीटीपीएल को यह भी संसूचित किया गया है कि तदर्थ अनुमोदन इस प्राधिकरण द्वारा आरंभ की गई परामर्श प्रक्रिया के परिणामों के अधीन होगा। 17 जुलाई 2019 के उक्त पत्र के द्वारा सीएचपीटी और सीसीटीपीएल को यह निर्देश भी दिया गया कि हमें नई प्रशुल्क प्रविष्टि के कार्यान्वयन की तारीख भी बतायी जाये।

5.2. इस संबंध में, सीसीटीपीएल ने 29 जुलाई 2019 के ई-मेल द्वारा यह संसूचित किया कि डीपीटी निर्यात कंटेनरों के लिए 15 दिन की निशुल्क भंडारण अवधि सीसीटीपीएल में 01 अगस्त, 2019 से प्रभावी की गई है।

6. निर्धारित परामर्शी प्रक्रिया के अनुसार, सीसीटीपीएल के 24 जून, 2019 के प्रस्ताव की एक प्रति संबंधित प्रयोक्ताओं/प्रयोक्ता संगठनों को हमारे 11 जुलाई, 2019 के पत्र के द्वारा उनकी टिप्पणियां प्राप्त करने के लिए भेजी गई। किसी भी प्रयोक्ता/प्रयोक्ता संगठन ने मामले की अंतिमता तक कोई टिप्पणी नहीं दी।

7. संदर्भाधीन मामले में चेन्नई में सीएचपीटी के परिसर में 2 अगस्त, 2019 को संयुक्त सुनवाई का आयोजन किया गया। संयुक्त सुनवाई में, सीसीटीपीएल तथा प्रयोक्ता/प्रयोक्ता संगठनों ने अपने-अपने निवेदन रखे।

8. इस मामले में परामर्श संबंधी कार्रवाई इस प्राधिकरण के कार्यालयी रिकॉर्ड में उपलब्ध है। संबंधित पक्षों द्वारा दिए गए मतों का सार उनको पृथक् रूप से प्रेषित किया जाएगा। ये विवरण हमारी वेबसाइट <http://tariffauthority.gov.in> पर उपलब्ध कराए जाएंगे।

9. मामले की प्रक्रिया के दौरान एकत्र की गई सूचना की समग्रता के आधार पर निम्नलिखित स्थिति उभर कर सामने आई:

- (i). चेन्नई कंटेनर टर्मिनल प्राइवेट लिमिटेड (सीसीटीपीएल) के मौजूदा दरमानों के अनुसार, सभी प्रकार के निर्यात कंटेनरों के लिए 7 दिन की निशुल्क अवधि मिलती है। सीसीटीपीएल ने बताया है कि सीधे पत्तन प्रवेश (डीपीई) कंटेनरों के प्रहस्तन की क्रियाओं के अनुसार निर्यातकों के टर्मिनल परिसर में कंटेनर जमा करके रखने पड़ते हैं। चूंकि निर्यातकों को इस मद पर निशुल्क दिवसों की समाप्ति के पश्चात् अतिरिक्त भंडारण प्रभार देने पड़ते हैं, इसलिए वे अपने कार्गो के निर्यात के लिए सीसीटीपीएल के प्रयोग से हिचकिचाते हैं क्योंकि अन्य छोटे टर्मिनल ज्यादा निशुल्क अवधि प्रदान करते हैं। इस प्रकार, डीपीटी ग्राहकों को सुविधाएं देने के उद्देश्य से, सीसीटीपीएल डीपीई ग्राहकों के लिए 7 दिन की मौजूदा निशुल्क अवधि को बढ़ाकर 15 दिन करने का प्रस्ताव लेकर आया है। यह बताया गया है कि प्रस्ताव डीपीई ग्राहकों के अनुरोध पर आधारित है।
- (ii). जैसा आदेश के पहले भाग में चर्चा की गई है, सीसीटीपीएल के संबंध में 25 मार्च, 2011 के पिछले प्रशुल्क आदेश पर माननीय चेन्नई उच्च न्यायालय ने रोक लगा रखी है। माननीय न्यायालय ने 19 जून, 2008 के यथाअनुमोदित प्रशुल्क आदेश के अनुसार उगाही करने की अनुमति दी है। सीसीटीपीएल यथाप्रस्तावित निशुल्क अविध में वृद्धि 19 जून, 2008 के आदेश में यथाअनुमोदित दरमानों के संदर्भ में है।
- (iii). प्रशुल्क दिशानिर्देश 2019 को कार्यान्वित करने के लिए जारी कार्यकारी दिशानिर्देशों का खंड 9.10.1 (जो सीसीटीपीएल के मामले में संगत है) व्यक्ति वीओटी प्रचालक को निशुल्क दिवस का प्रस्ताव करने की अनुमति देता है। तदनुसार, डीपीई कंटेनरों के लिए निशुल्क दिवसों में वृद्धि चाहने का सीसीटीपीएल का प्रस्ताव प्रशुल्क दिशानिर्देश 2019 में दी गई अनुवद्धताओं के भीतर पाया जाता है।

- (iv). लाइसेंस प्रदाता पत्तन, चेन्नई पत्तन न्यास (सीएचपीटी), ने सीसीटीपीएल के प्रस्ताव का समर्थन किया है और प्रयोक्ताओं ने भी सीसीटीपीएल के प्रस्ताव का अपना पूरा समर्थन दिया है।
- (v). प्रशुल्क दिशानिर्देश 2019 में अंतर्विष्ट अनुबद्धताओं के आधार पर और सीएचपीटी तथा प्रयोक्ता संगठनों द्वारा दिये गए समर्थन को देखते हुए यह प्राधिकरण सीसीटीपीएल के मौजूदा निशुल्क 7 दिनों को डीपीई कंटेनरों के लिए बढ़ाकर 15 दिन करने के प्रस्ताव को अनुमोदित करने को प्रवृत्त है।
- (vi). सीएचपीटी से प्राप्त टिप्पणियों के आधार पर सीसीटीपीएल को निशुल्क दिनों में तदर्थ आधार पर वृद्धि करने की अनुमति पहले ही दे दी गई है जो इस प्राधिकरण द्वारा आरंभ की गई परामर्शी कार्यवाही के परिणामों पर निर्भर करेगी। सीसीटीपीएल के प्रस्ताव पर न तो सीएचपीटी और न ही प्रयोक्ताओं को कोई आपत्ति है। सीसीटीपीएल ने संसूचित किया है कि डीपीई निर्यात कंटेनरों के लिए सीसीटीपीएल में 15 दिन का निशुल्क भंडारण 21 जून 2019 से कार्यान्वित कर दिया गया है। अतः डीपीटी निर्यात कंटेनरों के लिए निशुल्क दिनों की वृद्धि 01 अगस्त, 2019 से प्रभावी मानी जायेगी और तब तक वैध रहेगी जब तक प्रशुल्क दिशानिर्देश 2019 में अंतर्विष्ट अनुबद्धताओं के आधार पर सीसीटीपीएल के दरमानों की समीक्षा नहीं की जाती।

10.1. परिणाम में, और ऊपर बताये गए कारणों के लिए तथा सामूहिक विचार विमर्श के आधार पर, यह प्राधिकरण सीसीटीपीएल के दरमानों के भाग 3.11 के क्रमांक 2 की मौजूदा अनुसूची को निम्नलिखित से प्रतिस्थापित करने का अनुमोदन देता है:-

“

क्र.सं.	विवरण	विदेशगामी पोत			तटीय पोत		
		दर प्रति कंटेनर प्रति दिन या उसका भाग (अमरीकी डॉलर में)			दर प्रति कंटेनर प्रति दिन या उसका भाग (रु.में)		
2	निर्यात- एफसीएल, एलसीएल एवं खाली	20' तक	20'से अधिक और 40' तक	40'से अधिक	20' तक	20'से अधिक और 40' तक	40'से अधिक
	0-7 दिन	निशुल्क	निशुल्क	निशुल्क	निशुल्क	निशुल्क	निशुल्क
	8-15 दिन	5.50	11.00	16.50	231.00	462.00	693.00
	16-30 दिन	11.00	22.00	33.00	462.00	924.00	1386.00
	30 दिन से आगे	22.00	44.00	66.00	924.00	1848.00	2772.00
2(क)	डीपीई-एफसीएल	20' तक	20'से अधिक और 40' तक	40'से अधिक	20' तक	20'से अधिक और 40' तक	40'से अधिक
	0-15 दिन	निशुल्क	निशुल्क	निशुल्क	लागू नहीं		
	16-30 दिन	11.00	22.00	33.00			
	30 दिन से आगे	22.00	44.00	66.00			

”

10.2 सीसीटीपीएल को सलाह दी जाती है कि वे 19 जून, 2008 के प्रशुल्क आदेश में अनुमोदित अपने दरमानों में उपयुक्त संशोधन करें।

10.3. डीपीटी निर्यात कंटेनरों के लिए निशुल्क दिनों की वृद्धि 01 अगस्त, 2019 से प्रभावी मानी जायेगी और तब तक वैध रहेगी जब तक प्रशुल्क दिशानिर्देश 2019 में अंतर्विष्ट अनुबद्धताओं के आधार पर सीसीटीपीएल के दरमानों की समीक्षा नहीं की जाती।

टी.एस. बालसुब्रमनियन, सदस्य (वित्त)

[विज्ञापन -III/4/असा./256/19]

**TARIFF AUTHORITY FOR MAJOR PORTS****NOTIFICATION**

Mumbai, the 22nd October, 2019

**No. TAMP/32/2019-CCTPL.**—In exercise of the powers conferred under Section 48 of the Major Port Trusts Act, 1963 (38 of 1963), the Tariff Authority for Major Ports hereby disposes of the proposal received from Chennai Container Terminal Private Limited (CCTPL) for increasing the free days for Direct Port Entry (DPE) Export containers in its Scale of Rates, as in the Order appended hereto.

**TARIFF AUTHORITY FOR MAJOR PORTS**

Case No. TAMP/32/2019-CCTPL

The Chennai Container Terminal Private Limited

- - -

Applicant

**QUORUM**

- (i). Shri. T.S. Balasubramanian, Member (Finance)
- (ii). Shri. Rajat Sachar, Member (Economic)

**ORDER**

(Passed on this 10<sup>th</sup> day of October 2019)

This case relates to a proposal received from Chennai Container Terminal Private Limited (CCTPL) for increasing the free days for Direct Port Entry (DPE) Export containers in its Scale of Rates.

2.1. The Scale of Rates of CCTPL was last revised by this Authority vide Order No. TAMP/55/2009-CCTL dated 25 March 2011, wherein an across the board reduction of 35% was effected over the then prevailing tariff (i.e. tariff approved vide Order No. TAMP/45/2007-CCTPL dated 19 June 2008). The CCTPL has approached the Hon'ble High Court of Madras challenging the tariff order dated 25 March 2011 by its Writ Petition No. 12456 and 12457 of 2011. The Hon'ble High Court has stayed the tariff Order dated 25 March 2011 and has allowed the CCTPL to levy the tariff as approved vide tariff Order dated 19 June 2008.

2.2. In this backdrop, the CCTPL has now come up with a proposal proposing amendment in the storage schedule prescribed at Section 3.11 in the CCTPL Scale of Rates as approved vide the tariff Order No. TAMP/45/2007-CCTPL dated 19 June 2008.

3.1. The submissions made by CCTPL in its letter dated 24 June 2019 are as follows:

- (i). Direct Port Entry scheme was introduced by Central Board of Indirect Taxes & Customs vide circular F.No. 450/2009-Cus IV dated (07.09.2016) as a trade facilitation measure to reduce the release time of export containers and reduce cost of exports by allowing all factory stuffed/ self-sealed export containers to move directly into terminal prior LEO.
- (ii). However, utilizing the facility is becoming a challenge for exporter in managing the production vs dispatch of shipments when a shipment involves multiple containers and shipping bills. When part of the shipment / containers is ready for dispatch and the balance is still under process then containers / cargo have to be stored so that they can then be sent together or else dispatch has to be delayed which creates storage and dispatch capacity issues at factory increasing costs and difficulties.
- (iii). In order to avoid the above situation, the DPE Customers have requested CCTPL to extend the storage free period from 07 days to 15 days, as to dispatch cargo / containers on a continuous basis without attracting storage charges.
- (iv). The neighboring non-major Ports which are not under TAMP tariff regime are offering freedom even upto 30 days for DPE customers which influence majority of DPE customers diverting their containers through such private Ports.
- (v). As per CCTPL existing scale of rates (SOR) clause 3.11, export containers are eligible for 07 days free storage period. Thus, the CCTPL proposes to increase the free period for the DPE customers from the existing 7 days to 15 days.

3.2. The proposal of the CITPL is to introduce a new entry in the storage schedule as Sl no. 2(a) at Section 3.11 of its Scale of Rates. A comparative position of the existing and the proposed storage schedule is given below:

(a). Existing provision

Sr.No	Particulars	Foreign going Vessels			Coastal Vessels		
		Rate per container per day or part thereof (in US\$)			Rate per container per day or part thereof (in ₹.)		
		Upto 20' in length	Above 20' and upto 40' in length	Above 40' in length	Upto 20' in length	Above 20' and 40' upto 40' in length	Above 40' in length
2	Export – FCL, LCL & Empty						
	0-7 days	Free	Free	Free	Free	Free	Free
	8-15 days	5.50	11.00	16.50	231.00	462.00	693.00
	16-30 days	11.00	22.00	33.00	462.00	924.00	1386.00
	Beyond 30 days	22.00	44.00	66.00	924.00	1848.00	2772.00

(b). Proposed Provision

Sr.No	Particulars	Foreign going Vessels			Coastal Vessels		
		Rate per container per day or part thereof (in US\$)			Rate per container per day or part thereof (in ₹.)		
		Upto 20' in length	Above 20' and upto 40' in length	Above 40' in length	Upto 20' in length	Above 20' and 40' upto 40' in length	Above 40' in length
2	Export – FCL, LCL & Empty						
	0-7 days	Free	Free	Free	Free	Free	Free
	8-15 days	5.50	11.00	16.50	231.00	462.00	693.00
	16-30 days	11.00	22.00	33.00	462.00	924.00	1386.00
	Beyond 30 days	22.00	44.00	66.00	924.00	1848.00	2772.00
2.1	Export – Direct Port Entry Container (DPE)						
	0-15 days	Free	Free	Free	Free	Free	Free
	16-30 days	11.00	22.00	33.00	462.00	924.00	1386.00
	Beyond 30 days	22.00	44.00	66.00	924.00	1848.00	2772.00

3.3. Subsequently, the CCTPL vide its e-mail dated 06 August 2019 has conveyed that the charge with regard to coastal vessels is not relevant and has requested to drop prescription of charges for coastal vessels as proposed by it and approve its proposal for additional free days for container moving through foreign going vessels.

4.1. The proposal of CCTPL was forwarded vide our letter dated 27 June 2019 to the Licensor Port i.e., Chennai Port Trust (CHPT), seeking its comments.

4.2. In response, the CHPT vide its e-mail dated 16 July 2019 has conveyed the following:

- (i). The growth of the export containers in the two Terminals in Chennai Port has been affected with increased competition from Kattuppalli and Krishnapatnam ports attracting lines operating in Chennai Port.
- (ii). The Private Container Terminal Operators in other ports do this by giving considerable discount in Vessel Related Charges and additional facilities like free parking space, increased storage period for DPE containers etc., Export containers are easily attracted to these additional facilities mainly because of the easy access to Kattuppalli and Kamarajar Port Container Terminal since these ports are located in areas where roads are less congested and are away from City traffic.
- (iii). As part of the measures to arrest this trend, the terminals have proposed to increase the free period of storage of export containers from 7 to 15 days. They feel that this will enable some of the exporters to move the containers in advance and reach the terminals in Chennai in time to ensure vessel connectivity.
- (iv). At present they are not able to resort to this measure because of the restricted free period of 7 days in Chennai Terminals whereas neighboring private container terminals are providing 14-30 days free storage period for select Export customers.
- (v). In view of the above, the proposal of CCTPL, may be agreed to considering the interest of the Trade.

5.1. Based on the comments received from the CHPT, a letter no. TAMP/55/2009-CCTPL dated 17 July 2019 was issued to CCTPL conveying adhoc approval to CCTPL to insert Sr. No. 2.1 in Section 3.11 (Charges for Container Storage) of its Scale of Rates as brought out at Para no. 3.2 (b) above. It was also conveyed to CCTPL that the adhoc approval is subject to the outcome of the consultation proceedings to be initiated by this Authority. Vide the above said letter dated 17 July 2019, the CHPT and CCTPL were also directed to indicate, the date of implementation of the new tariff entry.

5.2. In this regard, the CCTPL vide its e-mail dated 29 July 2019 has conveyed that the free storage of 15 days for DPE export containers will be implemented at CCTPL with effect from 01 August 2019.

6. In accordance with the consultative procedure prescribed, a copy of the CCTPL proposal dated 24 June 2019 was forwarded to the concerned users/ user organizations vide our letter dated 11 July 2019 seeking their comments. None of the users / user organizations have given their comments till the case was finalized.

7. A joint hearing on the case in reference was held on 2 August 2019 at the premises of the CHPT at Chennai. At the joint hearing, CCTPL and users/ user organisation have made their submissions.

8. The proceedings relating to consultation in this case are available on records at the office of this Authority. An excerpt of the arguments made by the concerned parties will be sent separately to the relevant parties. These details will also be made available at our website <http://tariffauthority.gov.in>.

9. With reference to the totality of the information collected during the processing of this case, the following position emerges:

- (i). As per the existing Scale of Rates of the Chennai Container Terminal Private Limited (CCTPL), all types of Export containers enjoy a free period of 7 days. The CCTPL has stated that as per the modalities of handling of Direct Port Entry (DPE) Containers, it requires the exporters to accumulate and hold the containers at the terminal premises. Since the exporters incur additional storage charges after expiry of free days on this account, there is reluctance on the part of exporters to use CCTPL for export of their cargo, as other non-major ports give more number of free days. Thus, inorder to facilitate DPE customers, the CCTPL has come up with a proposal seeking an increase in the free days from the existing 7 days to 15 days, in respect of the DPE customers. The proposal is reported to be based on the request made by the DPE customers.
- (ii). As brought out in the earlier part of the Order, the last tariff Order dated 25 March 2011 in respect of CCTPL has been stayed by Hon'ble High Court of Madras. The Hon'ble Court has allowed the CCTPL to levy the tariff as approved vide tariff Order dated 19 June 2008. The increase in the free period as proposed by CCTPL, is with regard to the Scale of Rates as approved vide Order dated 19 June 2008.



- (iii). Clause 9.10.1 of the Workings Guidelines issued to operationalize the Tariff Guidelines, 2019, (which is relevant incase of CCTPL), allows the individual BOT operators to propose free days. Accordingly, the proposal of CCTPL seeking an increase in the free days for the DPE containers, is seen to be within the stipulation contained in the Tariff Guidelines, 2019.
- (iv). The Licensor port Chennai Port Trust (CHPT) has endorsed the proposal of the CCTPL and the users have also extended their support to the proposal of the CCTPL.
- (v). Based on the stipulation contained in the Tariff Guidelines, 2019, and considering the recommendation made by the CHPT and the user organization, this Authority is inclined to approve the proposal of the CCTPL to increase the free days for the DPE containers from the existing 7 days to 15 days.
- (vi). Based on the comments received from the CHPT, the CCTPL has already been allowed to increase the free days on an adhoc basis, subject to the outcome of the consultation proceedings initiated by this Authority. There was no objection to the CCTPL proposal either from the CHPT or from the users. The CCTPL has conveyed that free storage of 15 days for DPE export containers has been implemented from 01 August 2019. Thus, the provision relating to increase in the free days for DPE export containers is deemed to have come into effect from 01 August 2019 and shall remain valid till the Scale of Rates of CCTPL is reviewed based on the stipulations contained in the Tariff Guidelines, 2019.

10.1. In the result, and for the reasons given above, and based on a collective application of mind, this Authority accords approval to replace the existing schedule at Sl. no. 2 at Section 3.11 of the CCTPL Scale of Rates with the following:

“

Sr. No	Particulars	Foreign going Vessels			Coastal Vessels		
		Rate per container per day Or part thereof (in US\$)			Rate per container per day or part thereof (in ₹.)		
2	<b>Export – FCL, LCL &amp; Empty</b>	Upto 20'	Above 20' and 40'	Above 40'	Upto 20'	Above 20' and 40'	Above 40'
	0-7 days	Free	Free	Free	Free	Free	Free
	8-15 days	5.50	11.00	16.50	231.00	462.00	693.00
	16-30 days	11.00	22.00	33.00	462.00	924.00	1386.00
	Beyond 30 days	22.00	44.00	66.00	924.00	1848.00	2772.00
2(a)	<b>DPE-FCL</b>	Upto 20'	Above 20' and 40'	Above 40'	Upto 20'	Above 20' and 40'	Above 40'
	0-15 days	Free	Free	Free	Not Applicable		
	16-30 days	11.00	22.00	33.00			
	Beyond 30 days	22.00	44.00	66.00			

”

10.2 The CCTPL is advised to suitably amend the Scale of Rates approved in the tariff Order dated 19 June 2008.

10.3. The provision relating to increase in the free days for DPE export containers is deemed to have come into effect from 01 August 2019 and shall remain valid till the Scale of Rates of CCTPL is reviewed based on the stipulations contained in the Tariff Guidelines, 2019.

T.S. BALASUBRAMANIAN, Member (Finance)  
[ADVT.-III/4/Exty./256/19]